(d) The Government has taken the following steps to eliminate the use of DDT as pesticide:—

(i) Use of DDT has been reviewed by the Government from time to time since 1984. Consequently, its use in agriculture was withdrawn in May, 1989 and its use in public health programme is allowed upto 10,000 MT per annum.

(ii) A number of safer synthetic pesticides as well as biocides have been registered for use in public health programme. Besides, priority has been accorded for early registration of biocides.

(iii) The Central Government has cosntituted a Group in January, 1997 under the Chairmanship of Union health secretary to mandate the use of DDT in the public health programme. The use of DDT would be gradually reduced in phased manner under public health programme.

किसानों को नियंत्रण मुक्त उर्वरक बेचने हेतु धन का आबंटन

2121. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को किसानों को नियंत्रण मुक्त उर्वरक छूट पर बेचने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) किसानों को विनियंत्रित फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की बिक्री पर उर्वरक सप्लायरों को रियायत की राशि की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त बिक्री की प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त बिक्री की प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर गत दो वर्षों के दौरान किए गए भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	(लाख रुपए)
1994-95	2641.84
1995-96	3179.57

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

तिलहनों और दालों के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

2122. **श्री राम जेठमालनी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहनों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत दालों और तिलहनों के उत्पादकों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गत वर्षों के दौरान देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1995-96 के दौरान देश में दालों और तिलहनों की उत्पादकता दर क्या रही है; और

(ङ) 2002 ई० तक इन दरों में वृद्धि करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, हां। देश में दलहन एवं तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए दो केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी) एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी) चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न जरूरी आदानों जैसे बीजों के उत्पादन एवं वितरण, मिनिकिट का वितरण, राइजोबियम कृषि, जिप्सम/पाइराइट, उन्नत फार्म उपकरण, पौध संरक्षण उपकरण, किसान प्रशिक्षण, स्प्रिंकलर सेट इत्यादि के लिए इन दो फसलों के उत्पादकों को राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी

के स्थानान्तरण के लिए किसानों के खेत में अग्रिम एवं सामान्य प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(ग) और (घ) दलहन के मामले में, उत्पादन, जो आगे बढ़े बिना 14 मिलियन टन के आस पास रह रहा है, की अस्थिरता के लिए कई कारक जिम्मेवार हैं। तिलहन के मामले में हर वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ रिकार्ड उत्पादन करने में सफलता मिल रही है।

1990-91 के दौरान दलहन की उत्पादकता 578 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर थी जबकि 1995-96 के दौरान यह 551 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी। तिलहन के मामले में 1990-91 के दौरान उत्पादकता 771 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी और 1995-96 के दौरान 851 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी।

(ङ) 2002 ई० तक दलहन एवं तिलहनों की उत्पादकता दर में वृद्धि के लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Loss of cotton Production in Gujarat

2123. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that adverse weather conditions have affected Cotton production in Gujarat, particularly in the Saurashtra region, during 1996-97 season and Cotton growers have incurred heavy losses there from:

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government to mitigate the sufferings of Cotton growers of Gujarat, with details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) There has been no adverse weather conditions in Gujarat State. The produciton of Cotton in the state in fact is expected to be 28 lakh bales during 1996-97 which is 6 lakh bales higher than that during 1995-96.

(c) As a result of increased production/ supply, the prices of Cotton in Gujarat have declined in the current year, compares with last year, but these are ruling well above the minimum support levels. The State Government has asked the Gujarat State Cooperative Federation Ltd. (GUJCOT) to step up purchase of cotton from the farmers and has undertaken to bear losses, if necessary. The GUJCOT has so far purchased 1.33 lakh bales of cotton amounting to Rs. 129.50 crore.

The government of India has been taking various steps to help cotton growers:

(i) The minimum support prices (MSP) of various varieties were announced before the start of the season.

(ii) Export quota of 12.20 lakh bales of cotton has been released during the current year of which one lakh bales of cotton is alloted to GUJCOT. In addition spill-over quantity of 6.90 lakh bales (approx). from the export quota of 1995-96 season has been permitted to be exported by 28.2.97.

(iii) The Cotton Corporation of India (CCI) has been making aggressive purchases to give support to cotton growers. As on 23.2.97 the CCI purchases during the current season have been 7.81 lakh bales as compared to 6.14 lakh bales as on the corresponding date in the previous year. The CCI and GUJCOT have purchased 3.55 lakh bales and exported 1.69 lakh bales of cotton from Gujarat during the current season. State marketing Federation and NAFED have also given export quotas and have also been buying cotton.

(iv) The ceiling of export of cotton yarn of counts below 41s in 1996 was increased from 80 million kgs. to 110 million kgs. For the year 1997, the ceiling for export of cotton yarn below counts 41s has been further enhanced to 120 million kgs.

(v) Cotton has been removed from Selective Credit Control.

(vi) There are no on stock-limits for cotton.

(vii) In the Central Budge proposals for 1997-98, it has been proposed to repeal Ginning and Pressing Factories Act of 1925 and the Cotton Control